वीर अर्जुन

अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे, न दैन्यं, न पलायनम् ।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 25 जुलाई, 2024

पवार भ्रष्टाचार के सरगना, उद्धव औरंगजेब फैन क्लब प्रमुख

जैसे-जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं राजनीतिक दलों के स्वर तीखे होते जा रहे हैं। हाल ही के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जहां 2019 में राज्य की 23 सीटें जीती थीं, वहीं 2024 में घटकर यह नौ रह गई हैं। इससे भाजपा नेतृत्व बौखला गया और अब पूरी कसरत आगामी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने पर लगा दी है। नेताओं के स्वर न केवल तीखे होते जा रहे हैं बल्कि मर्यादाओं को लांघने वाले होते जा रहे हैं। प्रतिद्वंद्वियों पर हमले होते रहते हैं पर भाषा मर्यादित होनी चाहिए। रविवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार पर तीखा हमला किया और उन्हें देश में भ्रष्टाचार का सरगना करार दिया। पुणे में भाजपा के राज्य सम्मेलन में शाह ने शिवसेना (उद्धव) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख करार दिया और कहा कि वे 1993 के मुंबई श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन के लिए क्षमादान मांगने वालों लोगों के साथ बैठे हैं। शाह ने कहा कि भाजपा नीत महायुति महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2014 और 2019 के चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पुणे में कहा कि शरद पवार ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाया। शिवसेना (उद्धव) प्रमुख पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे उन लोगों के साथ बैठे हैं, जिन्होंने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन के लिए क्षमादान मांगा था। उन्होंने कहा कि औरंगजेब फैन क्लब क्या है? जो (26/11) के आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब को बिरयानी खिलाते हैं, जो याकूब मेमन के लिए क्षमादान

विकसित भारत बनाता सर्वस्पर्शी रोजगारोन्मुखी बजट

प्रो. रवीन्द्र गुप्ता

इस बजट को सही अर्थों में भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने वाला एवं सर्वस्पर्शी व रोजगारोन्मुखी बजट कहा जा सकता है।

मोदी सरकार का दूरगामी लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। अपने आप में यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, किंतु सरकार की मंशा और उसके अनुरूप कार्य देखते हुए असंभव भी नहीं है। हां, उसके लिए उस दिशा में धीरे-धीरे किंतु निरंतरता के साथ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। बजट 2024-25 भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य की दिशा में निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित होगा।

विकसित भारत के लिए सरकार ने 9 प्राथमिकताएं गिनाईं हैं:

1. खेती की उत्पादकता और अनुकूलता
2. रोजगार और कौशल प्रशिक्षण
3. मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. इंफ्रास्ट्रक्चर
8. इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट
9. अगली पीढ़ी के रिफॉर्म्स

इन 9 प्राथमिकताओं में पहले स्थान पर कृषि है। इसके लिए बजट में 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 2023-24 के बजट की तुलना में 8.5 प्रतिशत बढ़ा है। अगले 2 वर्षों में एक करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग देने का प्रावधान भी किया गया है जिसके अंतर्गत सर्टिफिकेट और ब्रांडेड भी की जाएगी। नेचुरल फार्मिंग के लिए 10000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

बजट पूर्णतया रोजगारोन्मुख है। रोजगार के नए अवसरों के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई है। उसका एक महत्वपूर्ण भाग इंटर्नशिप है जिसके माध्यम से देश की टॉप 500 कंपनियों में लगभग एक करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने का अनुमान है। यहां विशेष बात यह है कि यदि आवेदक के परिवार का सदस्य इनकम टैक्स देता है या कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो वह इंटर्नशिप के लिए आवेदन नहीं कर सकता। सामाजिक न्याय और समानता की दृष्टि से यह एक स्वागत योग्य शर्त है। रोजगार पैदा करने को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में ऐसी कंपनियों को, जो किसी को पहली बार नौकरी का अवसर देंगी, 2 साल तक उनकी एंप्लाइज प्रोविडेंट फंड देनदारी के लिए 3000 रुपए प्रति मास तक सरकार द्वारा देने की बात कही गई है। इससे 50 लाख नई रोजगार पैदा होने का अनुमान किया गया है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने वाले कर्मचारियों को रोजगार के पहले 4 वर्षों में सीधे कर्मचारियों और नौकरी देने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे 30 लाख युवाओं और एंपलायर्स को फायदा होगा। कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान देते हुए 5 साल में लगभग 20 लाख युवाओं को हुनरमंद बनाने का प्रस्ताव है ताकि स्वरोजगार की ओर युवाओं की मानसिकता बने और उस ओर झुकाव हो। साथ ही वे उद्योगों की ज़रूरतें भी पूरी कर सकें। आधुनिक तकनीक में भी लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को 2.2 लाख करोड रुपए की मदद घर के मद से पहुंचाई जाएगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है। बजट में 11.11 लाख करोड़ के पूंजीगत खर्च का प्रावधान है जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है। यह देश की ऊंची आर्थिक विकास दर का कारक और कारण दोनों है। इस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव सरकार की व्यवहारिक समझ दर्शाती है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

एंजल टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव स्टार्टअप निवेशकों के लिए और स्वयं स्टार्टअप के लिए अत्यंत सकारात्मक पहल है। एक लंबे समय से यह मांग की जाती रही है। भविष्य में उद्यमिता और स्टार्टअप को निश्चित ही एक ऊंची छलांग इसकी समाप्ति से मिलेगी।

मेक इन इंडिया नीति को ध्यान में रखते हुए देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेक उत्साह पूर्ण प्रस्ताव इस बजट में है। विशेष रूप से एमएसएमई (माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) के विकास की गति बने और वह प्रतिस्पर्धा का सही मुकाबला कर सकें, उसके लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम, असेसमेंट मॉडल, सहायता प्रोग्रेम आदि का प्रस्ताव किया गया है। यह निश्चित रूप से भविष्य में अच्छे परिणाम दायक होगा।

इनोवेशन व रिसर्च के बिना विकसित भारत की कल्पना बेमानी है। बजट में इसके लिए नेशनल इनोवेशन फंड बनाने की बात कही गई है। निजी क्षेत्र भी इसमें अपना योगदान दे, ऐसे उपाय किए गए हैं।

पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता किसी भी विकसित देश का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। इसी दृष्टि से ऊर्जा सुरक्षा पर बजट में काफी जोर दिया गया है। अक्षय ऊर्जा, जो देश में पर्याप्त मात्रा में है, उसका उपयोग बढ़ाने के लिए प्रस्ताव है। ऊर्जा का उपभोग दक्षता से हो इस पर भी ध्यान दिया गया है।

प्रत्यक्ष करों में भी नई रिजीम में टैक्स स्लैब्स में बदलाव करते हुए मध्यम वर्ग विशेष कर नौकरीपेशा वर्ग को अधिक नहीं तो कुछ राहत अवश्य मिली है। कॉरपोरेट टैक्स को 30 प्रतिशत से कम कर 25 प्रतिशत करना भी एक स्वागत योग्य कदम है। यह बाजार में पूंजी की तरलता बढ़ाएगा और इससे निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

कुल मिलाकर बजट 2024-25 विकसित भारत के लिए एक बहुप्रतीक्षित रोड मैप प्रदान करता है। यह रोजगार के नए अवसर खोलेगा। इसमें निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, कॉरपोरेट सेक्टर, शहरी वर्ग, किसान, विद्यार्थी, छोटा उद्यमी, श्रमिक, निवेशक इत्यादि सभी वर्गों के स्तरों को छूकर बेहतर बनाने की इच्छा शक्ति व प्रावधान किए गए हैं। इसी कारण इस बजट को सही अर्थों में भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने वाला एवं सर्वस्पर्शी व रोजगारोन्मुखी बजट कहा जा सकता है।

(लेखक : पीजीडीएवी कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल हैं।)